**उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल।**

**2009 के आदेश संख्या 294 से अपील**

**विजय कुमार.. अपीलार्थी।**

**बनाम**

**बैनी सिंह और अन्य।**

उत्तरदाताओं उपस्थितः अपीलकर्ता के वकील श्री गिरीश चंद्र लखचौरा।

सुश्री मेनका त्रिपाठी, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए।

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे। **दिनांकः 8 अप्रैल, 2022 निर्णय**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत आदेश से यह अपील से उत्पन्न होती है, जिसे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा 2007 के एमएसीपी केस नंबर 35, विजय कुमार सिंह बनाम बैनी सिंह और अन्य में दिए गए एक फैसले को दिया गया है, जिसके तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने दावेदार को मुआवजे की पात्रता के मुद्दे का निर्धारण करते समय, दावा याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिनांक 12 जून, 2009 के आक्षेपित अधिनिर्णय द्वारा अधिनिर्णय की एक राशि का प्रावधान किया गया था, जिसका मूल्यांकन दावाकर्ता को 3,18,800/– रुपये के रूप में देय होने के लिए निर्धारित किया गया था और दावा याचिका प्रस्तुत करने की तारीख से 9 प्रतिशत की दर से उस पर देय ब्याज भी दिया जाएगा।

**2.** मामले के तथ्य यह हैं कि 8 जनवरी, 2006 को जब दावेदार हल्दुआ साहू, जसपुर से ठाकुरद्वारा जा रहा था, रास्ते में उसकी साईकिल की टक्कर ट्रैक्टर ट्रॉली से हो गयी। ट्रैक्टर ट्रॉली का पंजीकरण संख्या यू0ए0–06डी–1628 था।दावाकर्ता की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष उठाई गई शिकायत यह थी कि जब वाहन के मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तक उसने यह दावा प्रस्तुत किया कि, दुर्घटना के कारण दावेदार को लगी चोटों की गंभीरता के कारण, उसे इलाज के लिए मेरठ ले जाया गया, जहां उसे एक सप्ताह की अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज चल रहा था और दुर्घटना के कारण उसे लगी चोटों के इलाज के लिए लगभग 2,00,000 रुपये का खर्च किया गया है और उसने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि उसका बायां पैर काट दिया गया था, इसलिए वह 80 प्रतिशत विकलांगता से पीड़ित था, जिसे तदनुसार डॉक्टर द्वारा प्रमाणित किया गया था, जो उसकी देखभाल कर रहा था। साइकिल की ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दुर्घटना हुई, जिसकी पंजीकरण संख्या यू.ए.–06डी/1628 है, जिसका क्लेमपीटिशन में दावेदार द्वारा यह तर्क दिया गया था कि दुर्घटना की तारीख को, ट्रैक्टरट्रॉली को वाहन के चालक द्वारा लापरवाही से चलाया जा रहा था, जिसने पीछे से क्लेमैंट को टक्कर मार दी, जिसके कारण, उसे गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह था। दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के पिछले पहियों

में फंस गया।

**3.** यद्यपि उक्त घटना की रिपोर्ट 20 जनवरी, 2006 को पुलिस के समक्ष दर्ज की गई थी, लेकिन अपीलकर्ता की शिकायत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष उठाई गई थी , जब वाहन के मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, तब यह दावा लेकर आया है। दुर्घटना के कारण दावेदार को लगी चोटों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए मेरठ ले जाया गया, जहां उन्हें एक सप्ताह की अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है। दुर्घटना के कारण उन्हें लगी चोटों के उपचार के लिए लगभग 2,00,000/– रुपये का व्यय किया गया और उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि उनका बायां पैर काट दिया गया था, इसलिए उन्हें 80 प्रतिशत विकलांगता से पीड़ित होने के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे डॉक्टर द्वारा प्रमाणित किया गया था, जो उनकी देखभाल कर रहे थे।

**4.** उपर्युक्त चिकित्सा व्यय के अलावा, उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि वह क्लेम याचिका में वर्णित मानसिक पीड़ा और अन्य संबद्ध मुआवजे के लिए पर्याप्त मुआवजे के हकदार होंगे और अधिनियम के प्रावधानों के तहत हकदार होंगे। दावा याचिका थी 3 ओपी नंबर 1 ने दावा याचिका का विरोध किया, यानी बैनी सिंह, जो दुर्घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक थे। उन्होंने पेपर नंबर 10 ख होने के नाते अपना विस्तृत लिखित बयान दाखिल किया था, और इस तथ्य को स्वीकार किया था कि दुर्घटना 18 जनवरी, 2006 को हुई थी, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक द्वारा जो अपवाद बनाया गया था, वह इस आधार पर था कि वह दावेदार को भुगतान किए जाने वाले किसी भी खर्च को पूरा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। दुर्घटना की तारीख तक वाहन को बीमा कवर नोट संख्या 080901/47/05/96/00000740 दिनांक 30 नवम्बर, 2005 के साथ वैध रूप से पंजीकृतकिया गया था, जो 29 नवम्बर, 2006 तक वैध था। उन्होंने आगे कहा कि दुर्घटना की तारीख पर, दावा याचिका पर वाहन के चालक, यानी ओपी नंबर 3 के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस था, जो 19 मई 2000 से 18 मई, 2000 तक वैध था , और इसलिए, उपरोक्त याचिका के आधार पर, चूंकि वाहन एक वैध दस्तावेज के तहत चलाया जा रहा था और बीमा कंपनी के साथ वैध रूप से बीमा किया गया था। यानी ओपी नंबर 1 और ओपी नंबर 3 ने मुआवजे के भुगतान को पूरा करने का बोझ बीमा कंपनी पर स्थानांतरित करने का प्रयास किया।

**5.** यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी ने पेपर नंबर 13ख होने के नाते अपना लिखित बयान दायर किया था, और तर्क दिया था कि चूंकि वाहन, मोटर वाहन अधिनियम के तहत निहित प्रावधानों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था, साथ ही बीमा की शर्तों का उल्लंघन कर रहा था, जो उल्लंघन करने वाले वाहन के पक्ष में जारी किया गया था। इस तथ्य के साथ युग्मित, कि चूंकि धारा 158 (1) के तहत निर्धारित समय के भीतर एक उपयुक्त जानकारी 4 मोटर वाहन अधिनियम की धारा, जिसे बीमा कंपनी को प्रदान नहीं किया

गया था, बीमा कंपनी को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाना चाहिए और चूंकि वाहन ओपी नंबर 3 द्वारा तेजी से और लापरवाही से चलाया जा रहा था, इसलिए वाहन का चालक, वास्तव में, यह वाहन का मालिक था, जिसे वहन किए जाने वाले खर्चों को वहन करना था और मुआवजे के रूप में देय बनाना था। दावेदार के लिए, यदि कोई हो।

**6.** कार्यवाही के पक्षकारों द्वारा उठाए गए अनुरोधों के पूर्वोक्त आदान–प्रदान के आधार पर, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए थे–

1. क्या इस न्यायाधिकरण को प्रस्तुत याचिका की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है ?

2. क्या दिनांक 18–1–2006 को समय करीब 9:00 बजे प्रातः पशुपति फेक्टी के पास ठाकुरद्वारा रोड थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद में टैंक्टर सं0यू0ए0–06डी0/1628 के चालकर द्वारा टैंक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर याची की साईकिल में टक्कर मार दी, जिससे याची को गम्भीर चोटें आयीं?

3. क्या दुर्घटना के समय टेंक्टर सं0 यू0ए0–डी/1628 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी डांईविंग लाइसेन्स नही था?

4. याची प्रतिकर की कितनी धनराशि और किस विपक्षी से प्राप्त करने का अधिकारी है ?

**7.** अपने–अपने तर्कों के समर्थन में, दावेदार ने खुद को पीडब्ल्यू 1 के रूप में गवाह बॉक्स में पेश करने और अपना बयान दर्ज करने के साथ–साथ पीडब्ल्यू 2 श्री मनोज कुमार और पीडब्ल्यू 3 श्री अमित कुमार के बयान दर्ज करके अपने साक्ष्य का नेतृत्व किया है और डॉक्टर, डॉ आर के को भी पेश किया था। दावेदार के रूप में उपस्थित डुंडारियाल, जब उनका इलाज चल रहा था और जिन्होंने पीडब्ल्यू 4 के रूप में अपना बयान दर्ज कराया। इसके अलावा, अतिरिक्त दस्तावेजों को सूची 6ग के माध्यम से रिकॉर्ड पर भी रखा गया था, जिसमें एफआईआर की प्रति, विकलांगता प्रमाण पत्र और सूची पेपर नंबर 17ग के माध्यम से उपचार के बिल, और पेपर नंबर 17ग/32 के माध्यम से पर्चे और अन्य सहायक दस्तावेज शामिल थे।

**8.** जहां तक वाहन के मालिक का संबंध है, उन्होंने भी लिखित बयान में लिए गए अपने रुख को मजबूत करने के लिए, यह स्थापित करने का प्रयास किया कि दुर्घटना की तारीख पर, वाहन को बीमा कवर की शर्तों के अनुसार वैध रूप से चलाया जा रहा था, और कागज नंबर 38ग के माध्यम से दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर भी रखा गया था। जिसमें बीमा पॉलिसी की जेरॉक्स कॉपी और दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक का ड्राइविंग लाइसेंस शामिल था।

**9.** उपर्युक्त दावों के आधार पर, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने तैयार किए गए मुद्दों के साक्ष्य की सराहना की, जिसे निर्धारित किया जाना था और अंततः, अपने निष्कर्ष को दर्ज करते समय, विशेष रूप से, अंक संख्या 4 के संदर्भ में, जो इस अपीलीय न्यायालय के लिए प्रमुख चिंता का विषय होगा, यह मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा देखा गया था। अंक संख्या 4 पर दर्ज अपने निष्कर्ष में, विशेष रूप से, यदि पुरस्कार के पैरा, 26 में की गई टिप्पणी का संदर्भ दिया जाता है, तो न्यायालय ने दावेदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के प्रभाव पर विचार किया है, चिकित्सा खर्चों के समर्थन में, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें 1 रुपये का खर्च आया है। 78,023/– और इसके अलावा अन्य अतिरिक्त खर्च, अर्थात मानसिक पीड़ा और पीड़ा, जो 6 दावेदार को अपने बाएं पैर के विच्छेदन के कारण नुकसान हुआ था, जिसमें उसके बाएं पैर के विच्छेदन के लिए देय मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये की अतिरिक्त राशि मांगी गई थी।

**10.** मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने मुआवजे की मात्रा का निर्धारण करते समय, जो देय होगा, अपने निष्कर्ष को पैरा 28 में दर्ज किया है और यह भी देखा है कि जहां तक दावेदार का संबंध है, वह एक सहायक के रूप में कार्यरत था और उपरोक्त कार्य से 4,500/– रुपये की राशि अर्जित कर रहा था। लेकिन चूंकि दावेदारों द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं रखा गया था कि उनके पास वास्तव में 4,500 रुपये की आय थी, इसलिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने दावेदार को प्राप्त आय निर्धारित की है, जो प्रति माह 2,000 रुपये है, लेकिन, यदि तर्कसंगत रूप से अपनाया गया था और निष्कर्ष जो पैरा 28 में दर्ज किए गए हैं, इस न्यायालय का विचार है कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा इस प्रकार का कोई तर्क नहीं दिया गया है कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा 2,000/– रुपये की आय का यह जादुई आंकड़ा कैसे निर्धारित किया गया और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अनुमानित आय का निर्धारण कैसे किया गया, जो कि अनुमानित आय के निर्धारण के लिए अपनाए जाने वाले बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत है। जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम की अनुसूची–1 के तहत प्रावधान किया गया है, और यह उस आधार पर है कि कुल वार्षिक आय 24,000 रुपये निर्धारित की गई थी, इसे 12 से गुणा करके और जिसमें से, प्रासंगिक कटौती करने के बाद, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा आय का आकलन 19 रुपये के रूप में किया गया है। 200/– रु की राशि जिसके बारे में कहा जा सकता है कि यह राशि किसको प्राप्त हुई है? 7 आवेदक, जिसे दुर्घटना की तारीख पर 28 वर्ष की आयु का माना गया था। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए सिद्धांतों के आधार पर भुगतान किए जाने वाले मुआवजे का विश्लेषण करते हुए, 2008 (2) टीएसी 394, लक्ष्मी देवी बनाम मोहम्मद तब्बर और अन्य में बताए गए निर्णय के अनुपात के आधार पर, 14 का गुणक लागू किया गया है और इसके परिणामस्वरूप, दावेदारों को देय कुल

मुआवजा 2,68,800 रुपये आंका गया है।

**11.** अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया था कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा अनुमानित आय के निर्धारण के लिए अपनाया गया मानदंड, निष्कर्षों के मद्देनजर, जिसे आक्षेपित निर्णय के पैरा 28 में दर्ज किया गया था, अपने आप में इस कारण से खराब है कि यदि मोटर वाहन अधिनियम के तहत निहित अनुसूची द्वारा निर्धारित अनुमानित आय, यदि इस पर ही विचार किया जाता है, तो देश की अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति दर के आधार पर देय अनुमानित आय का निर्धारण करने में आनुपातिक वृद्धि होनी चाहिए थी, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय में प्रतिपादित प्रमुख था, जिसे 2008 की सिविल अपील संख्या 2090 में प्रस्तुत किया गया था। लक्ष्मी देवी और अन्य बनाम मोहम्मद तब्बर और अन्य, जिसमें निर्णय के पैरा 4 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों द्वारा निर्धारित अनुपात के आधार पर यह निर्धारित किया था कि मोटर वाहन मोटर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित राष्ट्रीय आय का 15,000/– रुपये का बेंच मार्क, कल्पित आय के निर्धारण के लिए एक बार के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि 8 इसे समय बीतने के साथ आनुपातिक रूप से बढ़ाया और बदला जाना चाहिए क्योंकि उक्त अनुमानित आय को 1994 में अनुसूची–प्प में पेश किया गया था, और लगातार आर्थिक परिवर्तनों और मुद्रास्फीति दरों में वृद्धि के आधार पर और तदनुसार, पैरा 4 में दिए गए तर्क के आधार पर इसमें आनुपातिक वृद्धि होनी चाहिए थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि उपयुक्त अनुमानित आय 36,000/– रुपये प्रति वर्ष होगी। निर्णय का संगत पैरा 4 इस प्रकार है – उच्च न्यायालय ने मौत की लापरवाही के संबंध में पहले के निष्कर्षों की पुष्टि की। तथापि, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यद्यपि 4200/– रुपये प्रति माह की आय का दावा विश्वसनीय नहीं था, फिर भी अनुमानित आय 36,000/– रुपये प्रति वर्ष अर्थात 3,000/– रुपये प्रति माह मानी जानी चाहिए थी। इस प्रस्ताव के लिए उच्च न्यायालय ने कहा कि दूसरी अनुसूची में 15,000 रुपये की अनुमानित आय वर्ष 1994 में निर्धारित की गई थी, जबकि दुर्घटना वर्ष 2004 में हुई थी। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया दूसरा कारण यह था कि इन दिनों एक अकुशल श्रमिक भी आसानी से प्रतिदिन 100/– रुपये और 3,000/– रुपये प्रति माह कमा सकता है और इसलिए, उच्च न्यायालय ने आय को 36,000/– रुपये प्रति वर्ष माना और अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए मृतक की आय का 1/3 हिस्सा काटकर दावेदार निर्भरता का आकलन 24000/– रुपये प्रति वर्ष किया गया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा लागू 16 के गुणक को घटाकर 12 कर दिया। इस कार्रवाई के लिए, उच्च न्यायालय ने टीएन ट्रांसपोर्ट्स कॉर्पोरेशन के मामले में उपरोक्त फैसले पर भरोसा किया। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने 16 के बजाय 12 का गुणक लागू किया और अंततः उच्च न्यायालय 2,88,000 रुपये के आंकड़े पर पहुंचा और इसमें अंतिम संस्कार के खर्च, विधवा

को कंसोर्टियम के नुकसान और संपत्ति के नुकसान के कारण अन्य मुआवजा जोड़ा गया, जो ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया था और कुल मुआवजा 2 रुपये था। उच्च न्यायालय द्वारा 97,000/– रु की राशि प्रदान की गई थी। दावेदारों ने इस निष्कर्ष से असंतुष्ट होकर हमारे समक्ष यह अपील दायर की है।

**12.** दावेदार/अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के एक और निर्णय का उल्लेख किया है, जिसमें इस न्यायालय की विद्वान समन्वय पीठ ने 20 मार्च, 2014 को दिए गए अपने निर्णय में, 2012 के आदेश संख्या 309 से अपील में श्रीमती बसंती देवी और अन्य बनाम लखविंदर सिंह और अन्य, उसने पूरी तरह से एक अलग तर्क दिया था कि उपयुक्त अनुमानित आय का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए और उसमें यह देखा गया है कि यदि वेतन, जो राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के तहत दैनिक मजदूर को देय बनाया गया है और न्यूनतम मजदूरी के पहलू पर विचार करता है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, अकुशल श्रमिकों के लिए, जिसे विचार के लिए एक ठोस आधार के रूप में भी लिया जा सकता है, न्यूनतम वेतनमान निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में माना जा सकता है, जो किसी कर्मचारी की अनुमानित आय का आकलन करने के लिए बुनियादी मानदंड है, और इसलिए, मनरेगा की योजना के आधार पर उक्त निर्णय में, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मासिक राष्ट्रीय आय 4,500 रुपये प्रति माह की दर से निर्धारित की जानी चाहिए। निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार निकाला गया है:– "हालांकि, दावेदारों के मामले और पीडब्ल्यू 2 रवि कांत द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, बसंत राम मेसर्स झलानी ट्रेडर्स, रेलवे बाजार, हल्द्वानी में कार्यरत थे और उन्हें प्रति माह 8000 रुपये मिल रहे थे, हालांकि, पीडब्ल्यू 2 के बयान से यह साबित नहीं हो सका कि बसंत राम को प्रति माह 8,000 रुपये का वेतन मिल रहा था। मेरी राय में, काल्पनिक आय का पता लगाने के लिए, ट्रिब्यूनल को अकुशल श्रमिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा, नीचे 10 मनरेगा योजना के तहत गांव में रहने वाले प्रत्येक वयस्क को 150 रुपये प्रतिदिन की दर से 20 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यदि किसी दिहाड़ी मजदूर की अनुमानित आय के रूप में 150 रुपये प्रति दिन का आकलन किया जाता है, तो उसकी मासिक अनुमानित आय 4,500 रुपये प्रति माह होगी, इसलिए, बसंत राम की मासिक अनुमानित आय का आकलन किया जाना चाहिए था और इसके द्वारा इसे 4500 रुपये प्रति माह के रूप में मूल्यांकन किया जाना चाहिए था। चूंकि पांच व्यक्ति बसंत राम के मृतक पर निर्भर थे, इसलिए उनके व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/5 की कटौती की जानी चाहिए।

**13.** यदि आज के निर्णय के पूर्व भाग में इस न्यायालय द्वारा पहले ही देखे गए आक्षेपित अधिनिर्णय पर विचार किया जाता है, तो मुझे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई औचित्य और कोई व्यावहारिक तर्क दिखाई नहीं देता कि घायलों को प्राप्त अनुमानित आय 2 रुपये थी। (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात की तर्कसंगतता, जो अनुमानित आय 36,000/– रुपये प्रति वर्ष निर्धारित करती है, को मुआवजे के भुगतान के लिए सबसे सुरक्षित आधार के रूप में लिया जाना चाहिए था और वह भी घायल व्यक्ति की आयु के आधार पर गुणक की प्रयोज्यता के आलोक में, इस मामले में गुणक 28 वर्ष का होता है, जिसमें गुणक 14 निर्धारित किया गया है, जो अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क के अनुसार, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2009 (6) एससीसी 121 में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में निर्धारित सिद्धांत के विपरीत है। सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और एक अन्य, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने घायल या रोगग्रस्त व्यक्ति की आयु के आधार पर गुणक की प्रयोज्यता के सिद्धांत के पहलुओं के साथ निर्धारण करते समय यह देखा गया है कि 11 वर्तमान मामले में जिन परिस्थितियों पर विचार किया जा रहा है, जहां 80 प्रतिशत विकलांगता के परिणामस्वरूप गंभीर चोटों के दावे का मामला है, गुणक जो लागू किया जाना है, वह 17 का है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष संदर्भित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर देते हुए उक्त निर्णय के पैरा 42 में की गई टिप्पणी से स्पष्ट होगा। निर्णय के पैरा 42 को यहां उद्धृत किया गया है: "इसलिए हम मानते हैं कि उपयोग किए जाने वाले गुणक को ऊपर दी गई तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित होना चाहिए (सुसम्मा थॉमस, त्रिलोक चंद्र और चार्ली को लागू करके तैयार किया गया), जो 18 (15 से 20 और 21 से 25 वर्ष के आयु समूहों के लिए) के ऑपरेटिव गुणक से शुरू होता है, जिसे हर पांच साल के लिए एक इकाई से कम किया जाता है। यानी 26 से 30 साल के लिए एम–17, 31 से 35 साल के लिए एम–16, 36 से 40 साल के लिए एम–15, 41 से 45 साल के लिए एम–14 और 46 से 50 साल के लिए एम–13, फिर हर पांच साल के लिए दो यूनिट घटाया जाता है, यानी 51 से 55 साल के लिए एम–11, 56 से 60 साल के लिए एम–9, एम–7 61 से 65 साल के लिए और एम–5 66 से 70 साल के लिए।

**14.** उस स्थिति में, इस न्यायालय का विचार है कि तत्काल मामले में भी, यदि मुआवजे को शामिल परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाना आवश्यक था, तो वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत देय किया जाना चाहिए, जहां घायल /दावेदार अनुसूची के आयु स्लैब के भीतर 35 से 40 के बीच आ रहा था, इसे 16 के गुणक को लागू करने के प्रयोजनों के लिए आधार बनाना, सरला वर्मा (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत है और इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि सरला वर्मा निर्णय (सुप्रा) के व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों को अदालत में लागू करने के लिए आकर्षित किया जाएगा। 12 तत्काल मामला भी, और दावेदार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 17 गुणक के साथ दिए जाने का हकदार

होगा, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के लिए संदर्भित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देते हुए निर्धारित किया है।

**15.** काल्पनिक आय के निर्धारण पर आते हुए, मेरा विचार है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सिद्धांत, जैसा कि लक्ष्मी देवी (सुप्रा) के मामले में प्रस्तुत किया गया है, काफी तार्किक भी है और अनुमानित आय को बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए था, जैसा कि उक्त निर्णय के पैरा 4 में निर्धारित किया गया है, रु. 36,000/– प्रति वर्ष होगा।

**16.** उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित अधिनिर्णय में संशोधन किया जाता है और अपीलकर्ता की अनुमानित आय, जो कि कटौतियां करने के बाद 19,200/–रुपये निर्धारित की गई है, दावेदार द्वारा झेली गई विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर, 36,000/–रुपये की अनुमानित आय को देय मुआवजे का निर्धारण करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में लिया जाना चाहिए। तदनुसार, दावेदार को प्राप्त वास्तविक आय का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए 80 प्रतिशत विकलांगता के आधार पर कटौती की जानी है और सरला वर्मा (सुप्रा) के निर्णय द्वारा प्रदान किए गए गुणक के सिद्धांत के आधार पर इसे गुणक के सिद्धांत के आधार पर गुणा किया जाना है, और तदनुसार, उक्त आधार पर, दिनांक 12 जून, 2009 के आक्षेपित अधिनिर्णय को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि अपीलकर्ता को देय अनुमानित आय 36,000/–रुपये निर्धारित की जाएगी और सरला वर्मा (सुप्रा) के निर्णय के आधार पर इस पर गुणक का भुगतान 17 की दर से किया जाएगा ।

**17.** तदनुसार, आक्षेपित अधिनिर्णय को उस सीमा तक संशोधित किया जाता है। तदनुसार, आदेश से अपील, अपीलकर्ता के पक्ष में आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

**(शरद कुमार शर्मा, जे.)**

**08.04.2022**

शिव